बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–27.04.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संभावित पेयजल संकट से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–

1. **प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,**
2. **प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग**
3. **प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग**
4. **सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**
5. संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
6. **मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है। IMD द्वारा पूर्वानुमान में बताया गया है कि जून तक और गर्मी पड़ने की संभावना है। इस कारणवश भूगर्भ जल स्तर में गिरावट की सम्भावना है तथा पेय जल संकट उत्पन्न होने की भी संभावना हो सकती है।

1. **लघु जल संसाधन विभाग**

संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य के अन्तर्गत कुल 10242 नलकूपों में से 3897 नलकूप चालू हैं, जबकि पिछले सप्ताह चालू नलकूपों की संख्या 3831 थी। वर्त्तमान सप्ताह में यांत्रिक दोष से बंद नलकूपों की सं0 862, विद्युत दोष से बंद नलकूपों की सं0 649 संयुक्त दोष से बंद नलकूपों की सं0 2665 तथा अन्य दोष से बंद नलकूपों की सं0 2169 कुल 6345 है। इस सप्ताह में कुल 66 नलकूपों को चालू किया गया है।

संभावित पेय जल संकट के मद्देनजर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि पुराने बोरिंग की मरम्मति कराने के उपरान्त उसका फोटो अपने विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय, जिसमें अंकित अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं विद्युत दोष के कारण बंद पड़े नलकूपों की सूची ऊर्जा विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाए, जिससे विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों को चालू किया जा सके।

2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कुल 1640 पशु शिविर में उपलब्ध जल स्रोतो की संख्या 1467 है, जिसका भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। पशु चारा की समस्या नहीं है तथा राज्य स्तर पर पशुपालन निदेशालय में आपदा नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिसका दूरभाष सं0 0612– 2230942 है। इसी प्रकार निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष सं0 0612– 2224455 है।

मुख्य सचिव द्वारा शेष चिन्हित पशु शिविरों में उपलब्ध जल स्रोतों का भौतिक सत्यापन करने का निदेश दिया गया।

3. नगर विकास विभाग

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा बताया गया कि अभी तक किसी भी नगर निकाय से पेय जल संकट की सूचना नहीं है। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा के कुछ वार्डों में पेय जल संकट की सूचना मिली थी, जिसे दूर कर लिया गया है। High yielding tube well लगाया जा रहा है एवं पियाउ की व्यवस्था करने का निदेश नगर निकायो को दिया गया है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि शहरों में गरीबों को पानी पिलाने हेतु पियाउ सेंटर खोला जाए एवं इस हेतु मोबाईल पियाउ की भी व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव के द्वारा शहरी क्षेत्र में पेयजल पहुंचाने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को चार–पांच मॉडल प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिससे आवश्यकता के अनुरूप मॉडल प्राक्कलन के आधार पर पेयजल आपूर्त्ति हेतु व्यवस्था की जा सके।

4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य के दक्षिणी भाग के 17 जिलों का औसत भूजल में गिरावट मार्च 2016 की तुलना में 1–3′ के अन्तर्गत है, जिसमें पटना, नालन्दा, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, जमुई, भागलपुर एवं बांका में 0–1′, गया, नवादा, भोजपुर, शेखपुरा एवं लखीसराय में 1–2′ तथा औरंगाबाद में 2–3′ औसत भू–जल स्तर में गिरावट है। राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों में शिवहर, ढ़ाका, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी में 0–2′ तथा वैशाली में 2–3′ भूजल स्तर में गिरावट की सूचना है। शेष जिलो में औसत भूजल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जिलास्तर पर पदस्थापित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं को जिला पदाधिकारी के निदेश पर पेयजल संकट वाले ग्रामीण इलाके में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने का निदेश दिया जा चूका है।

संभावित पेय जल संकट के मद्देनजर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निदेशित किया गया कि पेयजल योजना अन्तर्गत 5–6 मॉडल प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के साथ तैयार कर लिया जाए, जिससे शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य सचिव के द्वारा पटना में पेयजल संकट के मद्देनजर दर्ज शिकायत एवं इसके विरूद्ध की गई

निष्पादित मामलों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाए, जिससे इसका सत्यापन कराया जा सके।

5. <u>ऊर्जा विभाग</u>

प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि युद्ध स्तर पर ट्यूबवेल का विद्युत दोष दूर करने की कार्रवाई की जा रही है। विद्युत दोष से पूर्व में बंद पड़े 3200 नलकूपों को ठीक कर लिया गया है तथा शेष 600 बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र ही ठीक कर लिया जायेगा। प्रधान सचिव के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से विद्युत दोष के कारण बंद पड़े पम्पों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जिससे विद्युत दोष को शीघ्र दूर किया जा सके।

मुख्य सचिव द्वारा विद्युत दोष से बंद पड़े राजकीय नलकूपों/पम्पों को शीघ्र चालू करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक **दिनांक 09.05.16 (सोमवार) को 5.30 बजे अपराह्न** में आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड)...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(संदीप कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड)/1255/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–29/04/2016

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

29/4/16

विशेष कार्य पदाधिकारी